www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 उपराष्ट्रपति चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम...

3 एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सेन्ट्रल बार में किया...

4 मोहनलाल बडौली की उपस्थिति में चीका नगर...

वर्ष: 9 | अंक: 297 | दिल्ली, गुरुवार, 21 अगस्त 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया नामांकन

नई दिल्ली (एजेन्सी)। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उन लोगों में शामिल थे, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन दाखिल करने गए। सूत्रों ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के तहत चार सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पहले सेट में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य प्रस्तावक थे। इससे पहले, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने संसद परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जहाँ प्रतिष्ठित हस्तियों की प्रतिमाएँ हैं। उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी की विशाल प्रतिमा के समक्ष नमन किया और फिर अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

असम में आईआईएम की स्थापना को लोकसभा की मंजूरी ऐतिहासिक अवसर: हिमंत

असम (एजेन्सी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) की स्थापना के लिए मंगलवार को लोकसभा में विधेयक पारित किया जाना एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए पूर्वोत्तर में शिक्षा केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि असम में पहले से ही एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) हैं। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, असम के लिए यह सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि लोकसभा ने राज्य का पहला भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आईआईटी, एम्स और अब आईआईएम के साथ, असम पूर्वी भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बनने की कगार पर है। आईआईएम-गुवाहाटी देश का 22वां और पूर्वोत्तर का दूसरा आईआईएम होगा।

जिला अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी के साथ छेड़खानी करने के आरोप में पत्रकार गिरफ्तार

नोएडा (एजेन्सी)। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में सोमवार रात को एक नर्सिंग अधिकारी से छेड़खानी करने के आरोप में एक यू-ट्यूब चैनल के पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। थाना सेक्टर 39 के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता जिला अस्पताल के महिला वार्ड में नर्सिंग अधिकारी है और उसने इस घटना के संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, महिला का आरोप है कि सोमवार देर रात शराब के नशे में धुत्त मनोज शर्मा नाम का व्यक्ति मेडिसिन के महिला वार्ड में आया और पीड़िता को जबरदस्ती वार्ड के पीछे ले जाने लगा तथा उसके साथ बदसलूकी एवं छेड़खानी की। सिंह ने शिकायत के हवाले से बताया कि महिला का शोर सुन वार्ड प्रभारी और सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गए और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया तथा इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी।

पीएम-सीएम हटाने वाले बिल पर संसद में बवाल, संयुक्त समिति को भेजा गया

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन विवादास्पद विधेयक पेश किए जिसके तहत लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाया जा सकता है। विपक्ष ने इस विधेयक को कठोर करार देते हुए दावा किया है कि सरकार इसका इस्तेमाल मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की मनमानी गिरफ्तारी के माध्यम से विपक्ष शासित राज्यों को अस्थिर करने के लिए करेगी। विधेयक की प्रतियां लोकसभा में फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंकी गईं।

इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष किसका विरोध कर रहा है,

विपक्षी सांसदों ने फाड़ी कॉपी, अमित शाह की ओर फेंके कागज

नैतिकता का या भ्रष्टाचार का? आखिरकार, भारतीय राजनीति में अगर हम नैतिकता के आधार पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफा देने की बात करते हैं, और फिर कानून बनाने की बात करते हैं, तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? आज लड़ाई साफ है। भ्रष्टाचारियों के साथ कौन खड़ा है- विपक्ष; और भ्रष्टाचार से मुक्त कौन है- भाजपा। विपक्ष और संसद में हुई ऐसी कार्रवाइयों ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है और यह भी दिखाया है कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

लोजपा (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि विपक्ष कभी किसी विधेयक पर चर्चा नहीं करना चाहता। जब उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलता है, तो वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर कागज फेंकते हैं, वह भी संसद के अंदर; फिर उनमें और अपराधियों में क्या अंतर है? यह बेहद चौंकाने वाला है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, विपक्ष ने गुंडागर्दी की हदें पार कर दी हैं. उन्होंने कागज फेंके और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया...मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा. मैं इस व्यवहार की निंदा करता हूं।

भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि टीएमसी के लोग संसद में हंगामा कर रहे थे। उनके साथ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्य भी अपनी सीटों पर बैठकर हंगामा कर रहे थे। हम संसद में रचनात्मक कार्य करने जाते हैं। अगर देश के गृह मंत्री कोई विधेयक लाए हैं, तो उनकी बात सुनना हमारा कर्तव्य है... हम इस तरह के व्यवहार की निंदा करते हैं।

भारतीय उत्पाद अमेरिका नहीं जाएंगे तो हमारे बाजार में आएंगे: रूस

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। दशकों से रूस भारत का सच्चा साथी बना हुआ है और भारत ने भी रूस का आड़े वक्त पर पूरा साथ दिया है। यही कारण है कि जब अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो रूस इसका विरोध कर रहा है। हम आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को रूस ने खुलकर "दोहरे मानदंड" बताते हुए भारत को आश्वस्त किया है कि उसके लिए रूसी बाजार हमेशा खुला रहेगा। रूस का यह कहना कि "भारतीय वस्तुएं यदि अमेरिकी बाजार में जगह नहीं पाएंगी तो वह रूस में जरूर जगह पाएंगी", भारत-रूस साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है। यह बयान केवल कूटनीतिक समर्थन ही नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी रेखांकित करता है।

हम आपको बता दें कि रूस के भारत स्थित दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ की तीखी आलोचना की है। यह टैरिफ भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर लगाया गया है। अमेरिकी दृष्टिकोण यह है कि रूस से तेल खरीदना, अप्रत्यक्ष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध के वित्तपोषण जैसा है। रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों को "दोहरे मानदंड" करार दिया

फाईल फोटो

और भारत पर तेल खरीद रोकने के लिए किए जा रहे दबाव को "अनुचित" बताया। यह बयान उस समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर मतभेद बढ़े हैं, विशेषकर डेयरी और कृषि क्षेत्र को लेकर।

रूस का तर्क है कि भारतीय रिफाइनरियों के लिए उसका तेल सबसे प्रतिस्पर्धी और लाभकारी है। रूस भारत को लगभग 5% छूट पर तेल उपलब्ध कराता है। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों ने सितंबर-अक्टूबर के लिए रूसी तेल की नई खेप खरीदने के अनुबंध किए हैं। यह खरीद उस समय फिर से शुरू हुई है जब छूट की दरें बढ़कर लगभग 3 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। हम आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने चीन और भारत जैसे देशों को भारी छूट पर तेल उपलब्ध कराना शुरू किया था। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और भारत ने आर्थिक व्यावहारिकता को देखते हुए रूसी तेल आयात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

देखा जाये तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से रूस एक विश्वसनीय भागीदार साबित हो रहा है। तेल और गैस आपूर्ति में विविधता लाना भारत की दीर्घकालिक नीति रही है ताकि पश्चिमी देशों या मध्य-पूर्व पर निर्भरता कम हो।

यमुना नदी को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए गठित की जाएगी संयुक्त कमेटी: नायब सिंह सैनी

प्रधानमंत्री के संकल्प अनुसार किया जाएगा यमुना को स्वच्छ: सीएम

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी ने कहा कि मां गंगा की तर्ज पर यमुना नदी को भी स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए सीडब्ल्यूसी, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। यह समिति यमुना नदी की सफाई के साथ-साथ इससे संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान पर भी कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की अध्यक्षता में इंटर स्टेट कॉर्डिनेशन रिलेटेड टू यमुना वाटर रेजुविनेशन को लेकर आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बैठक में केन्द्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने के बाद से योजनाओं को तीव्र गति से तैयार किया जा रहा है और उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि यमुना नदी की स्वच्छता के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। नदी में गिरने वाले गंदे पानी के नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के माध्यम से स्वच्छ करके नदी में प्रवाहित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना नदी की सफाई के अभियान के तहत अब तक 16 हजार मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प अनुसार निर्धारित लक्ष्य के तहत यमुना को स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यमुना की स्वच्छता दोनों सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शीघ्र ही जनता यमुना नदी का स्वच्छ रूप देख सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल जिले के पल्ला गांव से यमुना नदी में गिरने वाली ड्रेन का बीओडी स्तर 80 है। इस पानी को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के ओखला में यमुना नदी के पानी के बीओडी स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए 44 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 620 एमएलडी पानी शुद्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 510 एमएलडी पानी को स्वच्छ बनाने के लिए 9 और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण और पानी को लेकर किसी भी तरह की राज्यों की कोई सीमाएं नहीं होती। इसके लिए दोनों राज्यों को मिलकर कार्य करना होगा तभी यमुना नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं साफ बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदूषित पानी सीधे रूप से यमुना नदी में न डाला जाए। इसके लिए अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नजफगढ़ झील व ड्रेन की भी मॉनिटरिंग करने के लिए दिल्ली व हरियाणा के प्रतिनिधियों व विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी तथा हरियाणा के उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी के बीओडी लेवल की भी जांच की जाएगी।

श्री सैनी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की घोर निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बैठक में केंद्रीय सचिव देवश्री मुखर्जी, दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेन्द्र कुमार, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनित गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई विभाग अनुराग अग्रवाल सहित सिंचाई एवं पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विकसित दिल्ली निर्माण में कूड़े से बनी ऊर्जा और सड़कों की होगी अहम भूमिका: रविन्द्र इंद्राज

समाज कल्याण मंत्री ने बवाना जेजे कॉलोनी में चलाया स्वच्छता अभियान

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बुधवार को बवाना स्थित जेजे कॉलोनी में स्थानीय निवासियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 'दिल्ली को कूड़े से आजादी' अभियान में सक्रिय भागीदारी करें।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता को देश में एक जन आंदोलन का रूप दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आग्रह पर दिल्ली की जनता भी इस आंदोलन को नई दिशा दे रही है और अपने आस-पड़ोस को गंदगी व कूड़े से मुक्त कर रही है। श्री रविन्द्र इंद्राज ने कहा कि पूर्व सरकारों में कूड़ा सिर्फ पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन अब कूड़ा केवल अपशिष्ट नहीं, बल्कि विकास का ईंधन है। हाल ही में जनता को मिले अर्बन एक्सटेंशन रोड पर कूड़े से बनी सामग्री का प्रयोग सड़कों के निर्माण में किया गया है। दिल्ली में वेस्ट टू एनर्जी एवं अन्य नये प्लांट्स के जरिये कूड़े से बनने वाली बिजली और ईंधन, पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकार की योजनाओं से प्रदूषण कम होगा, घरों एवं वाहनों के लिए ईंधन मिलेगा, बिजली का उत्पादन होगा और सड़कें बनेंगी। विकसित दिल्ली निर्माण में यह मील का पत्थर साबित होगा। समाज कल्याण मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि खाली प्लॉट, नालियों या सड़कों पर कूड़ा न डालें, बल्कि डस्टबिन और नगर निगम के कूड़ा एकत्र करने वाले वाहनों में ही डालें। छात्र-छात्राएं भी इस अभियान में स्वच्छता दूत बनें और अपने परिवार व आसपास के लोगों को गंदगी फैलाने से रोकें। स्थानीय समितियां और निजी संगठन मिलकर स्वच्छता को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाएं।

श्री इंद्राज ने कहा कि जनसहयोग से चल रहे स्वच्छता कार्य केवल एक अभियान नहीं बल्कि दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित राजधानी बनाने का संकल्प है।

कोलकाता मेट्रो का नया अध्याय: 9 लाख से अधिक यात्री करेंगे हर दिन सफर

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आधारभूत संरचना में युगांतरकारी बदलाव हुए हैं। ऐसा ही बदलाव कोलकाता मेट्रो में भी हुआ है जहां प्रतिदिन 9 लाख से अधिक यात्रियों के सफर के लिए रेलवे नेटवर्क को विस्तृत किया गया है।

वस्तुतः भारत में मेट्रो सेवा की नींव रखने वाला शहर कोलकाता अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अब हर दिन कोलकाता मेट्रो से करीब 9.15 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। इस बदलाव की बुनियाद बनी है 3 मेट्रो सेक्शन की 366 नई मेट्रो ट्रेन सेवाएँ जो यात्रियों को तेज और नियमित सेवा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोलकाता मेट्रो की ग्रीन लाइन पर 2.45 किलोमीटर लंबी एस्प्लानेड-सियालदह मेट्रो सेक्शन, येलो लाइन पर 6.77 किलोमीटर लंबी नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेक्शन और ऑरेंज लाइन पर 4.4 किलोमीटर लंबी हेमंत मुखोपाध्याय-बेलेघाटा मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन करेंगे और तीनों ही लाइनों पर 3 मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

366 नई मेट्रो सेवाओं का सबसे बड़ा लाभ ग्रीन लाइन के यात्रियों को होगा। जिसपर सेवाओं की संख्या बढ़कर

186 हो गई है। साथ ही, ऑरेंज लाइन पर अब 60 सेवाएँ और येलो लाइन पर 120 सेवाएँ यात्रियों की राह आसान बनाएंगी। नई सेवाओं से अधिक ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ेगी, इंतजार का समय घटेगा और भीड़-भाड़ से राहत मिलेगी।

ग्रीन लाइन-एस्प्लानेड से सियालदह (2.45 किमी)। यह सेक्शन शहर के लिए सबसे बड़ी राहत लेकर आया है। अभी हावड़ा और सियालदह जैसे दो बड़े रेलवे टर्मिनलों के बीच पहुँचने में सड़क से 40-45 मिनट तक लगते हैं। अब मेट्रो से यह सफर सिर्फ.11 मिनट में पूरा होगा। रोजाना लाखों यात्रियों के लिए यह समय बचत किसी वरदान से कम नहीं होगी।

दूसरी बड़ी उपलब्धि है येलो लाइन-नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर (6.77 किमी)। अब एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए सड़क से यात्रा करने वालों को नया विकल्प मिलेगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री, एयरलाइन स्टाफ और एयरपोर्ट कर्मचारी सब तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव करेंगे। दमदम कैंटोनमेंट से इंटरचेंज सुविधा मिलने से पूरे शहर और प्रमुख रेलवे स्टेशनों तक सीधा कनेक्शन भी आसान हो जाएगा। एस्प्लानेड से एयरपोर्ट तक अब यह दूरी सिर्फ.30 मिनट में पूरी होगी।

तीसरी कड़ी है ऑरेंज लाइन-हेमंत मुखोपाध्याय से बेलेघाटा (4.4 किमी)। यह विस्तार साइंस सिटी, बड़े अस्पतालों, स्कूलों और व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ेगा। यात्रियों की संख्या यहाँ दोगुनी होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि बेलेघाटा से कवि सुभाष तक की यात्रा भी अब सिर्फ. 32 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इससे दक्षिण कोलकाता और पूर्वी कोलकाता के बीच सफर बेहद आसान हो जाएगा।

इन नई मेट्रो लाइनों से न सिर्फ. कोलकाता बल्कि उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के यात्रियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। जिस दूरी को तय करने में पहले घंटों लग जाते थे, अब वही सफर कुछ ही मिनटों में पूरा होगा। शहर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुँचना अब पहले से कहीं अधिक सहज और तेज हो जाएगा।

मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि 5' का सफल परीक्षण किया गया

नई दिल्ली (एजेन्सी)। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि 5' का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रक्षेपण ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। यह सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। अग्नि-5 एक लंबी दूरी की, परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। यह अग्नि श्रृंखला की सबसे उन्नत मिसाइल है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का एक परिवार है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सिविल लाइंस स्थित उनके कार्यालय में आयोजित 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। मुख्यमंत्री के कार्यालय ने यह जानकारी दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आरोपी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा। इसके बाद, आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। उत्तर दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाईजी के रूप में हुई है। हमले के मकसद का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।

इस घटना के बाद, उत्तर दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुख्यमंत्री कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस अप्रत्याशित घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

सम्पादकीय

ट्रंप ने खोया भरोसा

यह तो भविष्य के गर्व में छिपा है कि रुस यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देशों का क्या निर्णय होगा या युद्ध कब तक समाप्त होगा या सहमति के हालात बनेंगे या नहीं पर एक बात साफ हो गई है कि अमेरिका के लोगों को ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय को लेकर भरोसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय 81 प्रतिशत अमेरिकियों को भरोसा था कि ट्रंप द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वह भरोसे लायक होगा। यानी कि वह सोच समझ भरा निर्णय होगा। कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका के 81 फीसदी नागरिक यह मानकर चल रहे थे कि ट्रंप द्वारा रुस यूक्रेन युद्ध को लेकर लिया जाने वाला निर्णय भरोसे लायक होगा। राष्ट्रपति बनने के बाद से जिस तरह से ट्रंप द्वारा एक के बाद एक तुगलकी निर्णय लिए जा रहे हैं और जिस तरह से विश्व के देशों को धमकाना शुरू किया है उससे ट्रंप ने स्वयं के साथ ही अमेरिका की फजीयत ही अधिक कराई है। विश्व का दादा बनने के प्रयास में ट्रंप और अमेरिका दोनों की ही साख में तेजी से गिरावट आई है। ट्रंप–पुतिन मुलाकात के बाद भी साफ हो गया है कि कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है और भले ही यूक्रेन की जेलेंस्की को ट्रंप ने चर्चा के लिए अमेरिका बुलाया हो और बातचीत भी हुई हो पर लब्बोलुबाब तो यही रहेगा कि इस मुलाकात के बाद अमेरिका की हेटी तो साफ दिखाई दे ही रही है। इससे पहले जेलेंस्की और ट्रंप की गत मुलाकात के समय जिस तरह से अमेरिका की हेटी हुई वह भी सबके सामने हैं। भले ही पुतिन जेलेंस्की मुलाकात करने को राजी हो गये हो पर सीज फायर हो भी गया तो वह स्थाई सीजफायर होगा इसमें पूरी तरह से संदेह है। इन हालातों में प्यू रिसर्च द्वारा हाल ही किये गये सर्वे में जो परिणाम सामने आये हैं वह किसी विश्व नेता के लिए शर्मनाक से कम नहीं होने चाहिए। 81 प्रतिशत भरोसे लायक नेता पर 40 प्रतिशत अमेरिकीयों का भरोसा और इनमें से भी 25 प्रतिशत का थोड़ा भरोसा तो फिर देखा जाए तो केवल 15 प्रतिशत अमेरिकी ही ट्रंप पर पूरी तरह से भरोसा जता रहे हैं। 59 प्रतिशत अमेरिकीयों को तो ट्रंप पर अब बिलकुल भी भरोसा नहीं रहा है। देखा जाए तो दुनिया के देश तो ट्रंप की बेजा हरकतों से परेशान है ही वहीं अमेरिकावासियों को भी अमेरिका का भविष्य कोई अच्छा संकेत देता नहीं लग रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के एक के बाद लिए गए फैसलों ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बना दिया है। ट्रंप की हर धमकी हवा हवाई बनकर रह गई है। इसके साथ ही ट्रंप द्वारा कही जाने वाली बात कब तक रहेगी इस पर भी दुनिया के लोगों को संदेह होने लगा है। एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप किसी मसखरें की छवि में दुनिया के देशों के सामने आ रहे हैं। टैरिफ वार सामने हैं। टैरिफ के नाम पर देशों को धमकाना ज्यादा नहीं चल सकता, यह अमेरिका को समझना होगा। भारत पर 40 प्रतिशत टैरिफ लगाने से उलटा मोदी को मजबूत बनाने का काम ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है। इससे पहले जिस तरह से कनाडा को अपना 51 वां राज्य कहना दादागिरी का बड़ा नमूना है। भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान सीजफायर करने के दावें की पोल खुल चुकी है। देखा जाए तो ट्रंप तानाशाही रवैया अपनाते हुए दुनिया के देषों को ड़राने धमकाने में लगे हुए हैं। हांलाकि चाहे टैरिफ नीति हो या उपनिवेशवादी सोच देर सबेर इसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा और गत बैठक के दौरान व्हाईट हाउस में ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस और नोकझोंक से दुनिया के देशों में साहस का संचार हुआ है। व्हाइट हाउस की घटना का तात्कालिक परिणाम ही यह सामने आ गया है कि यूरोप के देश एक स्वर में यूक्रेन के साथ खड़े होने लगे है तो दूसरी और अपना नया नेता चुनने पर विचार करने लगे हैं। हांलाकि जेलेंस्की ने देश हित को पहली वरियता दी है और अमेरिका से अब भी खनिज संपदा के अधिकार देने पर सहमति समझौता करने को लगभग तैयार है। पर अमेरिका दबाव बनाकर और डरा धमकाकर समझौता करना चाहता है यही कारण है कि समझौते क प्रारुप पर चर्चा करने आये जेलेंस्की को ही रुस यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार बताते हुए तीखी नोंकझोंक तक हालात पहुंच गए और जेलेंस्की की हिम्मत की इसलिए सराहना करनी होगी कि अमेरिका के आगे नाक रगड़ने की जगह वार्ता छोड़कर यूरोपीय देशों की यात्रा पर आ गये। भविष्य में क्या होता है यह तो अलग बात हैं पर चाहे रुस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे इजरायल हमास या फिर भारत पाक ट्रंप किसी बहुरूपिये की तरह से एक्सपोज हो गए हैं। इससे रुस और पुतिन का विश्व राजनीति में उभार का अवसर मिला है वही दुनिया के देशों की कोरोना व अन्य नीतियों के कारण चीन के प्रति बनी सोच में भी बदलाव आने लगा है। इसके साथ ही दुनिया के देशों में आज भारत की छवि भी बदलाव आया है और भारत को सशक्त और दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम देश के रुप में देखा जाने लगा है। टैरिफ वार के नाम पर भारत को धमकाना और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ लंच करने से अमेरिका और ट्रंप दोनों की साख नकारात्मक रुप से प्रभावित हुई है। ट्रंप के निर्णय के यही हालात रहे तो अमेरिका हाशियें में आ जाएं तो कोई अनपेक्षित बात नहीं होगी। ऐसे में ट्रंप के सलाहकारों को यह समझाना होगा कि ड़राने धमकाने का या दादागिरी का समय नहीं रहा है छोटा से छोटा देश अपनी अस्मिता के लिए लंबा संघर्ष करने में पीछे हटने वाला या झुकने वाला नहीं हैं।

जयंती

गोपाल कृष्ण देवधर

जन्म–21 अगस्त, 1871, पुणे, महाराष्ट्र; मृत्यु–1935) भारत के प्रसिद्ध समाज सेवक थे। राजनीतिक गतिविधियों की ओर इनका ध्यान कम था। गोपाल कृष्ण देवधर जहाँ कहीं भी सेवा का कोई अवसर देखते, वहाँ तुरंत पहुँच जाते थे। महात्मा गाँधी द्वारा स्थापित 'अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ' के प्रादेशिक अध्यक्ष का पद गोपाल कृष्ण जी ने आजीवन सम्भाला था। 'सेवा सदन' की स्थापना में भी उन्होंने रमाबाई रानाडे को अपना पूरा सहयोग दिया था।

पुण्यतिथि

विष्णु दिगम्बर पलुस्कर

जन्म: 18 अगस्त, 1872; मृत्यु: 21 अगस्त, 1931) हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा थे, जिन्होंने भारतीय संगीत में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। वे भारतीय समाज में संगीत और संगीतकार की उच्च प्रतिष्ठा के पुनरुद्धारक, समर्थ संगीतगुरु, अप्रतिम कंठस्वर एवं गायनकौशल के घनी भक्त हृदय गायक थे। विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर रामधुन गाकर हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। पलुस्कर ने लाहौर में 'गंधर्व महाविद्यालय' की स्थापना कर भारतीय संगीत को एक विशिष्ट स्थान दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने समय की तमाम धुनों की स्वरलिपियों को संग्रहित कर आधुनिक पीढ़ी के लिए एक महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

कल मिलेंगे

बीवी ने प्यार से पति का सिर दबाते हुए पूछा–शादी से पहले कौन दबाता था?
पति बोला, शादी से पहले सिर दर्द होता ही नहीं था.
बीवी की बोलती हो गई बंद!

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।
RNI No. : DELHIN/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

उपराष्ट्रपति चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता की सियासी लड़ाई बनाने के रणनीतिक मायने

तीसरा, बीजेपी नीत एनडीए के लिए दक्षिण भारत में अपनी जड़ें जमाना अब भी मुश्किल भरा कार्य है। चूंकि कर्नाटक में उसकी जमी–जमाई सियासी जड़ें भी सूखती चली गई, इसलिए उसकी राजनीतिक मुश्किलों को समझा जा सकता है। जबकि विपक्ष की सियासत के लिए दक्षिण भारत शुरू से ही एक ऐसा उर्वर राजनीतिक मैदान, रहा है, जहां से उसने भाजपा को सदैव मजबूत चुनौती पेश की है

-कमलेश पांडेय

उपराष्ट्रपति पद के लिए अब एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। एनडीए ने जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं उनसे मुकाबले के लिए इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी. सुदर्शन रेड्डी को चुनाव मैदान में उतारा है। इस प्रकार एक तरफ जहां मोदी ने एनडीए उम्मीदवार की तारीफ करते हुए कहा है कि राधाकृष्णन सियासी खेल नहीं करते हैं, बल्कि सुलझे हुए राजनेता हैं। वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार रेड्डी को गैरराजनीतिक चेहरा बताते हुए कहा है कि मौजूदा चुनाव विचारधारा (संघ बनाम प्रगतिशील) की लड़ाई है। साधारण भाषा में कहें तो उपराष्ट्रपति चुनाव को भी राष्ट्रवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता की सियासी लड़ाई का नया अखाड़ा बना दिया गया है, जिसके रणनीतिक मायने भी दिलचस्प हैं।

यूँ तो संख्या बल में एनडीए यानी सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी है, लेकिन यह लड़ाई आंकड़ों से ज्यादा प्रतीकात्मक प्रतीत होता है। देखा जाए तो अपने-अपने सियासी अहम के सवाल पर विभाजित विपक्ष ने भी पुनः एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक मजबूत प्रत्याशी उतारकर सत्तापक्ष को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वह किसी मोर्चे पर सरकार को फ्री हैंड नहीं देने जा रहा है। उसके इस कदम से विपक्ष को फायदा हो या न हो, लेकिन एनडीए में शामिल दलों की पूछ परख बढ़ जाएगी। वहीं, किसी भी सहयोगी ने यदि थोड़ा सा घात कर दिया तो फिर सत्ता पक्ष की किरकिरी भी हो सकती है। यही वजह है कि मौजूदा उपराष्ट्रपति चुनाव के दृष्टिगत कतिपय सवाल खड़े हो रहे हैं- खासकर उम्मीदवार चयन को लेकर। सर्वप्रथम तो यह कि जिस तरह से दोनों केंद्रीय सियासी गठबंधनों ने अपने-अपने उम्मीदवार के नाम दक्षिण भारत से दिए हैं, उससे भी उत्तर भारत के राजनेता ठगे रह गए हैं। उल्लेखनीय है कि सर्वसम्मति से एनडीए कैंडिडेट बने राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, जबकि सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना (पुराने आंध्रप्रदेश) से। लिहाजा, दोनों चेहरों का दक्षिण भारत से होना महज सियासी संयोग नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे दोनों प्रतिस्पर्धी राजनीतिक गठबंधनों की कोई सुनियोजित राजनीतिक योजना है और इसी वजह से यह चुनाव और भी अधिक दिलचस्प हो जाता है।

दूसरा, विपक्षी दल एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार रेड्डी की लड़ाई को विचारधारा यानी धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई बता रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जब एनडीए संघ के आदमी पर भरोसा कर रहा है तो वो एक प्रोग्रेसिव विचारधारा यानी धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार को सामने रख रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंच से एक संक्षिप्त से नोट पढ़कर इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रेड्डी के नाम का ऐलान किया, वह खासा अहम है।

जैसा कि खरगे ने कहा है कि सभी दलों ने सर्वसम्मति से रेड्डी की उम्मीदवारी पर मुहर लगाई है। यह विपक्षी एकता के लिहाज से लोकतंत्र के लिए एक बड़ा क्षण है। लिहाजा, उन्होंने रेड्डी को राजनीतिक न्याय का चैंपियन करार दिया। जबकि मंच से ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि इस फैसले में आम आदमी पार्टी भी ब्लॉक के साथ है। बताया गया है कि इंडिया ब्लॉक के अंदर सभी दलों के साथ इस मसले पर गत सोमवार और मंगलवार सुबह अनौपचारिक बातचीत हुई थी।

दरअसल, इस पूरी प्रक्रिया में चार-पांच नामों को लेकर सोमवार को चर्चा भी हुई, पर वह किसी ना किसी वजह से पूरे मापदंड पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। इसी दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व निदेशक और तमिलनाडु से आने वाले माइलस्वामी अन्नादुरई और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी के नामों पर चर्चा की। जब इन अहम नामों पर भी आम सहमति नहीं बन पाई, तब मंगलवार दोपहर को खरगे की ओर से सभी घटकों के नुमाइंदों के सामने रेड्डी का नाम सामने रखा गया, जिस पर किसी की ओर से आपत्ति नहीं जताई गई।

बताया जाता है कि रेड्डी का नाम कांग्रेस शासित तेलंगाना की सोशल इंजीनियरिंग से भी जुड़ा रहा है। वहां की सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षण के डेटा के विश्लेषण के लिए जिस पैनल का गठन किया था, उसकी अगुआई रेड्डी ने ही की है। वहीं, टीएमसी जैसे दलों की ओर से यह साफ कर दिया गया था कि इंडिया ब्लॉक की ओर से उम्मीदवारी में जो भी व्यक्ति सामने आए, वह गैर राजनीतिक हो। इसलिए रेड्डी के नाम पर आम सहमति बन गई। बताया जाता है कि टीएमसी नेत्री व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमिलनाडु के नेता स्टालिन से कहा था कि चुनाव को तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु बनाने का अच्छा संकेत नहीं जाएगा। फिर बात आई कि बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को चुना जाए। इस पर कहा गया कि इसे बीजेपी दक्षिण में भुना लेगी। फिर छोटे राजनीतिक नाम से भी परहेज करने पर सहमति बनी। तब सबमें सहमति जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नाम पर हुई। इससे कांग्रेस को लगता है कि वह इस नाम को पेश कर आंध प्रदेश में भी अपनी साख जमा सकती है।

चूंकि, विपक्ष गठबंधन की दक्षिणी राज्यों के दलों पर भी नजर है। विपक्ष के एक नेता ने कहा भी है कि उन्हें उम्मीद है कि वाईआरसीपी अब अपने रुख पर फिर से विचार करेगा। बता दें कि वाईआरएसीपी ने गत सोमवार को ही घोषणा की है कि वह उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे। इसे विपक्ष राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का काउंटर मान रही है, जिसके जरिए एनडीए, डीएमके जैसे दलों को सोच में डालना चाहता है।

तीसरा, बीजेपी नीत एनडीए के लिए दक्षिण भारत में अपनी जड़ें जमाना अब भी मुश्किल भरा कार्य है। चूंकि कर्नाटक में उसकी जमी-जमाई सियासी जड़ें भी सूखती चली गई, इसलिए उसकी राजनीतिक मुश्किलों को समझा जा सकता है। जबकि विपक्ष की सियासत के लिए दक्षिण भारत शुरू से ही एक ऐसा उर्वर राजनीतिक मैदान, रहा है, जहां से उसने भाजपा को सदैव मजबूत चुनौती पेश की है। इसलिए कहा जा सकता है कि जारी उपराष्ट्रपति चुनाव में इस पद के लिए घोषित उम्मीदवार रेड्डी पूर्व निर्धारित सियासी लड़ाई का विस्तारित रूप ही है। खासकर जिस तरह से एनडीए सहयोगी टीडीपी ने इंडिया ब्लॉक प्रत्याशी राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान किया है, उसका प्रभावी असर भी अब सत्ता पक्ष की रणनीति पर साफ-साफ दिखने भी लगा है और प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों से भी उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी राधाकृष्णन के लिए सहयोग मांगा है। उनके लिए खुशी की बात यह है कि इंडिया ब्लॉक के डीएमके ने एनडीए प्रत्याशी राधाकृष्णन का समर्थन करने का फैसला किया है।

इसलिए कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहा चुनाव दोनों केंद्रीय सियासी गठबंधनों के लिए मौका और चुनौती दोनों लेकर आया है। अगर सौ फीसदी वोटिंग होती है, तो दोनों सदनों में मिलाकर चुनाव में जीत के लिए 394 वोट चाहिए होंगे। जबकि एनडीए के पास 422 का संख्या बल है। चूंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है और सदस्य पार्टी व्हिप से नहीं बंधे होते हैं। इसलिए सरकार और विपक्ष, दोनों के शक्ति प्रदर्शन के लिए यह मौके के साथ साथ चुनौती भी है। यही वजह है कि दोनों राजनीतिक गुट की तरफ से अपने अपने समर्थन का दायरा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। खासतौर पर दक्षिण से आने वाले क्षेत्रीय दलों पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों की नजरें होंगी। बताया जा रहा है कि मौजूदा उपराष्ट्रपति चुनाव में वैचारिक टकराव भी बढ़ेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद किसी पार्टी का नहीं होता। इसलिए यदि इसकी गरिमा को देखते हुए अगर सर्वसम्मति से किसी को चुना जाता, तो ज्यादा अच्छा रहता।

हालांकि अभी की राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसी संभावना दूर-दूर तक नजर नहीं आती है। देश में पिछले कुछ बरसों से जिस तरह का तनातनी भरा राजनीतिक माहौल है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ज्यादातर मौकों पर दो विपरीत ध्रुवों पर नजर आते हैं। वहीं, जिन मामलों में सदन में सहमति की मांग थी, वहां भी सहमति नहीं बल्कि असहमति दिखी। जबकि यह तो चुनाव तय ही था, जहां वैचारिक लड़ाई व उससे निकलने वाला अंजाम दोनों ही महत्वपूर्ण है।

चूंकि उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा के सभापति के दृष्टिगत एक अहम जिम्मेदारी भी समझी जाती है। इसलिए इस पद के इर्द-गिर्द हाल के महीनों में बहुत असाधारण हलचल देखने को मिली है। यही वजह है कि निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिन हालात में और जैसे गए, उसे तो कदापि अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि यह चुनाव बेहतर माहौल में और इस पद के सम्मान को देखते हुए उसके हिसाब से लड़ा जाएगा। जीत जिसकी भी हो, उस पर लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को आगे ले जाने की अहम जिम्मेदारी होगी। फिर भी यह सवाल मौजूं है कि एक देश, एक चुनाव का नारा देने वाली भाजपा व उसके सहयोगियों ने देश पर यह चुनाव असमय क्यों थोपा?

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चीन की ढील अस्थायी राहत है, समाधान आत्मनिर्भरता में छिपा है

भारत इस बात को समझ रहा है इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और लिथियम बैटरियों के स्वदेशी उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाये थे। हम आपको याद दिला दें कि भारत सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम के अंतर्गत PLI ACC योजना शुरू की थी। 18,100 करोड़ रुपये की इस योजना का लक्ष्य 50 गीगावाट घंटा उत्पादन क्षमता विकसित करना है

नीरज कुमार दुबे

चीन द्वारा हाल ही में लगाए गए और फिर हटाए गए रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात प्रतिबंध ने भारत की औद्योगिक ढाँचे की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों की प्रगति जिन महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भर है, उनमें भारत आज भी भारी मात्रा में आयात पर आश्रित है। चीन का वर्चस्व और उसकी नीतिगत अनिश्चितता भारत जैसे देश के लिए केवल आर्थिक चुनौती ही नहीं, बल्कि रणनीतिक खतरा भी है।

चीन द्वारा निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भारतीय उद्योगों को झटका दिया था। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में उत्पादन और नई परियोजनाओं पर संकट खड़ा हो गया था। हालाँकि, चीन ने अब इन प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे तत्काल राहत मिली है, लेकिन इसने यह भी साफ कर दिया कि यदि भारत समय रहते आत्मनिर्भर नहीं बना तो भविष्य में ऐसी स्थितियाँ बार-बार सामने आ सकती हैं।

भारत इस बात को समझ रहा है इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और लिथियम बैटरियों के स्वदेशी उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाये थे। हम आपको याद दिला दें कि भारत सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम के अंतर्गत PLI ACC योजना शुरू की थी। 18,100 करोड़ रुपये की इस योजना का लक्ष्य 50 गीगावाट घंटा उत्पादन क्षमता विकसित करना है। इसमें से 40 गीगावाट घंटा क्षमता पहले ही विभिन्न कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। यह क्षमता न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों बल्कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल और रक्षा क्षेत्र को भी मजबूत करेगी। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि भारत लिथियम बैटरियों के क्षेत्र में धीरे-धीरे आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू वैल्यू चेन तैयार करेगा।

इसके अलावा, खनन मंत्रालय ने रणनीतिक खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय समझौते किए हैं। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी, कोट डी आइवरी जैसे खनिज-संपन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जा रहा है। साथ ही भारत ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे संगठनों के साथ भी साझेदारी की है। यह सहयोग न केवल कच्चे खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और निवेश के क्षेत्र में भी मददगार होगा।

इन सभी प्रयासों से तीन महत्वपूर्ण संदेश निकलते हैं। पहला यह है कि चाहे बैटरी निर्माण हो या रेयर अर्थ मैग्नेट्स का उत्पादन, भारत को अपनी घरेलू वैल्यू चेन विकसित करनी ही होगी। दूसरा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता की बजाय भारत को खनिजों की आपूर्ति के लिए बहुस्तरीय और बहु-देशीय नेटवर्क खड़ा करना होगा। तीसरा है कि यदि भारत वास्तव में ई-मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व चाहता है तो उसे केवल आयात पर आधारित रणनीति से आगे बढ़कर संपूर्ण स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना होगा।

जहां तक यह सवाल है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्यों खास हैं तो आपको बता दें कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स अब तक के सबसे शक्तिशाली स्थायी चुम्बक माने जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है उच्च चुंबकीय क्षमता और डिमैग्नेटाइजेशन (चुंबकत्व खत्म होने) के प्रति प्रतिरोध। इन्हें बनाने में मुख्यतः नियोडिमियम, प्रसीओडिमियम, और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इनकी मजबूती और हल्के वजन की वजह से ये छोटे आकार वाले, ऊर्जा-कुशल और आधुनिक उपकरणों के लिए अपरिहार्य हैं। वहीं सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैग्नेट है नियोडिमियम-आयरन-बोरोन मैग्नेट।

हम आपको बता दें कि चीन के पास दुनिया की लगभग 70% रेयर अर्थ मेटल्स खनन और करीब 90% मैग्नेट उत्पादन का नियंत्रण है। चीन की ताकत सिर्फ खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी सप्लाई चेन–खनन, प्रसंस्करण, मिश्र धातु उत्पादन और मैग्नेट निर्माण–पर काबिज है। पिछले 6-8 वर्षों में इन मैग्नेट्स की मांग तेजी से बढ़ी है क्योंकि ये सामान्य फेराइट/पारंपरिक चुम्बकों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ, हल्के और प्रभावी हैं।

भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 2025-26 में लगभग 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत होगी, जबकि देश की कुल मांग लगभग 3,600 टन अनुमानित है। ICE और EV वाहनों में इनका इस्तेमाल स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ई-एक्सल, वॉटर पंप, ट्रांसमिशन किट, स्पीकर्स, सेंसर और इग्निशन कॉइल जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों में होता है। चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारतीय कंपनियों को आयात में कठिनाई हुई, जिससे उत्पादन बंद होने और नई लॉन्चिंग टलने का खतरा पैदा हो गया। अब प्रतिबंध हटने से इंडस्ट्री को भारी राहत मिलेगी, खासकर त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए।

बहरहाल, चीन की ढील से भारत को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसने यह भी याद दिला दिया है कि रणनीतिक खनिजों की सुरक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता से कहीं आगे जाकर राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह यात्रा तभी सफल होगी जब बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए घरेलू उत्पादन और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित हो।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे मॉस्को, अज्ञात सैनिक की समाधि पर अर्पित की श्रद्धांजलि

(एजेन्सी)। **विदेश** मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को मॉस्को स्थित अज्ञात सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐतिहासिक स्मारक पर यह श्रद्धांजलि उनकी रूस यात्रा के दौरान दी गई। अपनी यात्रा के व्यापक कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि उन्हें रूस के प्रमुख विद्वानों और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके खुशी हुई, जहाँ उन्होंने भारत-रूस संबंधों और व्यापक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत-रूस संबंधों, समकालीन विश्व भू-राजनीति और भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर मंगलवार से गुरुवार तक रूस की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान, वह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे और व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता भी करेंगे। एक आधिकारिक बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री की यह यात्रा रूसी संघ के प्रथम उप प्रधान मंत्री डेनिस मंटुरोव के निमंत्रण पर हो रही है। डॉ एस जयशंकर, 20 अगस्त 2025 को निर्धारित व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता करने के लिए 19-21 अगस्त 2025 को रूस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। विदेश मंत्री मॉस्को में भारत-रूस व्यापार मंच की बैठक को भी संबोधित करेंगे। बयान के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे।

3236 लाख करोड़ के कर्ज में फंसा अमेरिका! दुनिया को हिलाने चले ट्रंप को ले डूबा टैरिफ बम

(एजेन्सी)। **डोनाल्ड** ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। रूस से तेल क्यों लेते हो ये कहकर आंखें दिखा रहे हैं। नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो जल्दी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अमेरिका के लोग और पूरी दुनिया के लोग ये मान लें कि वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उन जैसा अमेरिका का कोई राष्ट्रपति कभी हुआ नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया पर टैरिफ बम गिराकर उसे हिलाने का सपना देख रहे हैं। अमेरिका जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर वन पर है। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है।

अमेरिका सुपरपावर होकर भी बुरे आर्थिक जाल में फंसा हुआ है। अपने ही बोझ तले दबा हुआ है। वो बोझ कर्ज का है। दुनिया को धौंस दिखाने वाला अमेरिका आज खुद अपने कर्ज के बोझ तले बुरी तरह कराह रहा है।

ट्रंप तेजी से उभरते देशों की अर्थव्यवस्था को डगमगाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। आज उन्हीं का देश कर्ज के मकड़जाल में बुरी तरह फंस गया है। दरअसल, अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी और उससे भी कहीं ज्यादा 37 ट्रिलियन डॉलर का राष्ट्रीय कर्ज है। इसे अगर भारतीय रुपये में बदलकर देखें तो करीब 3 हजार 236 लाख करोड़ रुपए बैठ रहा है। यानी हर अमेरिकी नागरिक के सिर पर लगभग 1 लाख डॉलर भारतीय रुपए में 87 लाख रुपए से ज्यादा का बोझ है। इस हालात में भी डोनाल्ड ट्रंप उभरते देशों पर टैरिफ लगाकर उन्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असलियत यही है कि जिन देशों को ट्रंप टैरिफ लगाकर गिराने का प्रयास कर रहे हैं वहीं देश अपनी स्थिरता के दम पर खुद आगे भी बढ़ रहे हैं।

एशिया कप के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान

(एजेन्सी)। **बिहार** के राजगीर में होने वाले एशिया कप हॉकी के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान बुधवार को किया गया। जिसमें फॉरवर्ड शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह ने अपनी जगह बरकरार रखी है। टूनामेंट 29 अगस्त से सात सितंबर तक खेला जाएगा जिसके विजेता को अगले साल एफआईएच पुरुष वर्ल्ड कप में सीधे प्रवेश मिलेगा जो 14 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड और बेल्जियम में होगा।

ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान हैं। राजिंदर सिंह, लाकड़ा और दिलप्रीत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा थे। राजिदंर को शमशेर सिंह की जगह चुना गया, जबकि लाकड़ा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कहने वाले ललित उपाध्याय की जगह ी है। दिलप्रीत को गुरजंत सिंह पर तरजीह मिली है।

स्ट्राइकर ललित उपाध्याय ने जून में एफआईएच प्रो लीग के यूरोप चरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया था। भारत को एशिया कप में जापान, चीन और कजाखस्तान के साथ पूल ए मिला है। भारतीय टीम 29 अगस्त को चीन के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। इसके बाद 31 अगस्त को जापान और एक सितंबर को कजाखस्तान से खेलना है।

गोलकीपिंग का दारोमदार कृशन बी पाठक और सूरज करकेरा पर होगा। डिफेंस में हरमनप्रीत और अमित रोहिदास के साथ जरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगाज सिंह हैं। मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राजिंदर, राज कुमार पाल और हार्दिक सिंह होंगे। फॉरवर्ड पंक्ति में मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, लाकड़ा और दिलप्रीत जिम्मा संभालेंगे। नीलम संजीप सेस और सेल्वम कार्ति को रिजर्व में रखा गया है।

भारतीय टीम इस प्रकार है-

गोलकीपर-सूरज करकेरा, कृशन बी पाठक।

डिफेंडर-हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगराज सिंह।

मिडफील्ड-मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद,राजिंदर, राज कुमार पाल और हार्दिक सिंह।

फॉरवर्ड-मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह।

रिजर्व खिलाड़ी-नीलम संजीप सेस और सेल्वम कार्ति।

एनआर नारायण ने 10 हजार से खड़ी की अरबों की इंफोसिस

(एजेन्सी)। **इंफोसिस** के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति आज यानी की 20 अगस्त को अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें कि साल 1981 में एनआर नारायण मूर्ति और उनके साथी इंजीनियरों ने इंफोसिस की स्थापना की थी। इस कंपनी की स्थापना में एनआर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति का भी अहम योगदान रहा है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एनआर नारायण के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था, जब उन्होंने लगातार 120 घंटे भूख का अनुभव किया था। इस घटना के बाद एनआर नारायण को इंफोसिस का आईडिया आया। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर एनआर नारायण मूर्ति के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में....कर्नाटक के सिदलघट्टा में एक मिडिल क्लास हिंदू परिवार में 20 अगस्त 1946 को एन आर नारायण मूर्ति का जन्म हुआ था। उन्होंने साल 1967 में राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। फिर 1969 में आईआईटी कानपुर से मास्टर डिग्री ली।

इसके बाद उन्होंने नौकरी का रुख किया और साल 1970 में पेरिस में काम करने चले गए। इस दौरान उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इसमें से एक प्रोजेक्ट चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर एयर कार्गो हैंडलिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना शामिल था। इसके बाद वह भारत वापस लौट आए और पुणे की एक कंप्यूटर सिस्टम कंपनी में नौकरी करना शुरूकर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया, जिसने आगे चलकर देश की आईटी सेक्टर में क्रांति ला दी।

साल 1981 में अपने 6 साथियों के साथ मिलकर नारायण मूर्ति ने कंपनी शुरू करने का प्लान किया। इस कंपनी का नाम इंफोसिस रखा गया था। इसके लिए नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति 10 हजार रुपए उधार लिए थे। शुरूआती दिनों में ही पुणे के ही एक छोटे से अपार्टमेंट से इंफोसिस चलाया जा रहा था।

'अब पैंट पहनने में भी होती है मुश्किल'–अमिताभ बच्चन

(एजेन्सी)। 82 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन अपनी बेजोड़ ऊर्जा और समर्पण से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति की मेजबानी से लेकर फि ल्मी भूमिकाएँ निभाने तक, सुपरस्टार हमेशा की तरह सक्रिय रहते हैं। लेकिन सुर्खियों के पीछे, बिग बी ने अब बढ़ती उम्र की छिपी चुनौतियों के बारे में बात की है। एक बेबाक ब्लॉग पोस्ट में, शोले अभिनेता ने बताया कि कैसे उनका शरीर सुस्त पड़ रहा है और कैसे अब रोजमर्रा के कामों के लिए भी अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। मुंबई में प्रशंसकों के साथ अमिताभ बच्चन का रविवार का मिलना-जुलना एक लोकप्रिय कार्यक्रम है, लेकिन यह रविवार थोड़ा अलग था क्योंकि अमिताभ बच्चन ने इसके बाद अपने दैनिक कार्यक्रम के बारे में लिखा। 82 वर्षीय अमिताभ ने बताया कि कैसे अब उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी काम के साथ-साथ दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या से भी ज्यादा प्रभावित होती है। अभिनेता ने बताया, "कुछ रूटीन जो पहले थे, उन्हें देखकर लगता है कि चूँकि ये कुछ साल पहले किए गए थे, इसलिए इन्हें फिर से शुरू करना बहुत आसान होगा। नहीं... नहीं बेबी। बस एक दिन की अनुपस्थिति, और दर्द और गतिशीलता बहुत लंबी सैर के लिए चली जाती है। यह आश्चर्य की बात है कि पहले जो सामान्य क्रियाएँ होती थीं, अब उन्हें करने से पहले दिमाग को सोचना पड़ता है।

एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सेन्ट्रल बार में किया वाटर कूलर का लोकार्पण

सेन्ट्रल बार में वाटर कूलर का लोकार्पण करते हुए स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा (दुपट्टा ओढ़े हुए)। (छायाः एसबी)

एसबी संवाददाता

वाराणसी। बुधवार को स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के सभागार में अपने विधायक निधि से अधिवक्ताओं को शुद्ध पेयजल के लिए वाटर कूलर का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर सेन्ट्रल बार के अध्यक्ष मंगलेश दूबे, महामंत्री राजेश गुप्ता, उपाध्यक्ष दीपक राय कान्हा, आलोक सौरभ, विधु प्रकाश पाण्डेय, मोनू चौबे, सतीश यादव, रंजन मिश्र गौतम कुमार झा आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।

शहीद हरमिंदर सिंह की अंतिम अरदास पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए

■ शहीद हरमिंदर सिंह के भाई को सरकारी नौकरी देने की घोषणा, गाँव में बनेगा स्मारक

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़/अमलोह। श्रीनगर के कुलगाम जिले में शहीद हुए भारतीय सेना के जांबाज सिपाही स्व. हरमिंदर सिंह नमित्त पाठ का भोग एवं अंतिम अरदास आज गाँव बदीनपुर में हुई, जिसमें पंजाब सरकार की ओर से रक्षा सेवाएं कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी एवं बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत विशेष रूप से श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने शहीद हरमिंदर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी बहादुरी को सलाम किया और कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहाँ शहीदों की कुबार्नी को नमन करती है, वहीं शहीद परिवारों की आर्थिक मदद के लिए भी वचनबद्ध है।

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा शहीद हरमिंदर सिंह के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है, जिसके तहत आज परिवार को 6 लाख रुपये का चेक सौंपा गया है और दस्तावेजी

प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही परिवार को शेष 94 लाख रुपये की सहायता राशि भी प्रदान कर दी जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार द्वारा शहीद के भाई को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, ताकि भविष्य में यह परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि 28 वर्षीय शहीद हरमिंदर सिंह की शहादत से न केवल माता-पिता और गाँववासियों का बल्कि पूरे पंजाब और देशवासियों का सिर गर्व से ऊँचा हुआ है। शहीद देश का गौरव होते हैं और जो इंसान देश के लिए कुर्बानी देता है, उसे दुनिया हमेशा याद रखती है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने शहीद के पिता सहित अन्य परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि हर सुख-दुख की घड़ी में सरकार परिवार के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन माता-पिता के बच्चे देश की आन-बान और शान बनाए रखने के लिए शहादत देते हैं, उनसे महान कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा शहीद हरमिंदर सिंह की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए गाँव में विशेष स्मारक बनाया जाएगा।

इस अवसर पर अमलोह विधायक गुरिंदर सिंह गैरी बडिंग ने परिवार की ओर से संगत का धन्यवाद किया। उन्होंने शहीद हरमिंदर सिंह की शहादत को नमन किया और परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि फौजी जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिनकी बदौलत हम सब चैन की नींद सोते हैं।

इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉ. सोना थिंद, जिला पुलिस प्रमुख शुभम अग्रवाल, जिला योजना समिति के चेयरमैन अजय सिंह लिबड़ा, जिला रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के बलजिंदर सिंह विर्क, नगर परिषद अध्यक्ष हरप्रीत सिंह प्रिंस समेत बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, प्रशासनिक, पुलिस और सेना के अधिकारी, गाँव और शहरों के गणमान्य लोग मौजूद रहे और शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

गिद्धौर में राजस्व महा अभियान में घर घर पहुंच रही अंचल की टीम

■ 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाया जा रहा अभियान

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई/गिद्धौर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान प्रारंभ हो गया है। इसी कड़ी में जिले के संबंधित अंचलों से जुड़े पंचायत एवं गांव में जमाबंदी पंजी वितरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

बताते चलें कि जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार द्वारा इस अभियान की निगरानी की जा रही हैं, यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक निरंतर चलेगा, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जमीन संबंधी दस्तावेजों का त्रुटि सुधार के साथ नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करवाना है। अंचल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक हल्का क्षेत्र में सात दिनों के अंतराल पर दो शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में सभी आवेदन को स्वीकार कर उनका निस्तारण किया जाएगा। इस कार्य को ले जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को माइक्रोप्लान के अनुसार कार्य करने करने निर्देश दिया है। वहीं इस कार्य को ले

अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को अपने क्षेत्र का लगातार अनुश्रवण करना है। सभी अंचल अधिकारियों को प्रतिदिन का प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसकी प्रति जिला राजस्व शाखा में जमा करने का दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है।

झाझा विधानसभा में घर-घर पहुंच जदयू कर रही सरकार के विकास कार्यों का गुणगान

■ योजनाओं की जानकारी दे लाभ लेने की जदयू कार्यकर्ता कर रहे अपील

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई/गिद्धौर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के निकटता को देखते हुए बिहार में एनडीए समर्थित जदयू नेतृत्व की सरकार में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ले चलाए जा रहे जनहितकारी योजनाओं से आम लोगों को घर-घर जाकर उन योजनाओं से उन्हें रूबरू कराया जा रहा है। इसी कड़ी में जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को गिद्धौर प्रखंड के पतसंडा बाजार में जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा घूम घूम कर सरकार के योजनाओं से जुड़कर आम लोगों के को लाभ लेने के लिए कार्यकर्ता उनसे मिल उन्हें विकास योजनाओं को ले उन्हें जागरूक कर रहे हैं। इसी जदयू पंचायत अध्यक्ष अशोक केशरी व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष अजित कुमार के संयुक्त नेतृत्व में पतसंडा पंचायत में जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर सरकार के योजनाओं से जुड़ा रिपोर्ट कार्ड जनता को समर्पित कर बिहार के विकास को लेकर निरंतर किए जा रहे बदलाव एवं कारगर प्रयास से उन्हें अवगत कराया जा रहा है।

इस मौके पर कार्यक्रम को लेकर पंचायत अध्यक्ष अशोक केशरी व्यवसाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजित कुमार ने मौके पर संयुक्त रूप से कहा कि एनडीए साझेदारी में बिहार के मुखिया सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्व मंत्री सह वर्तमान जदयू विधायक दामोदर रावत के नेतृत्व में आज झाझा विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युतीकरण, तकनीकी शिक्षा, आधारभूत

झाझा विधानसभा के गिद्धौर बाजार में नीतीश सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराते जदयू कार्यकर्ता। (छायाः एसबी)

संरचना, कृषि हितकारी, पशुपालन, जीविका, कुशल युवा कार्यक्रम, पेंशन योजना सहित कई योजनाओं से आम जनमानस को सीधा जोड़कर उन्हें शहरीकरण के इस दौड़ में गांव वासियों को विकसित कर बिहार बदलाव की दिशा में नए नए कृतिमान गढ़ रही है। ताकि आने वाले दिनों में देशीय स्तर पर बिहार के विकास की एक लंबी लकीर खींची जा सके।

वहीं मौके पर जदयू नेता नियाज खान ने कहा कि नीतीश सरकार के नेतृत्व पर भरोसे का ही यह प्रतिफल है कि आज बिहार नित्य दिन नई नई बुलंदियों को छू रहा है, आप सब का साथ यू हीं बना रहा तो देश में बिहार अन्य राज्यों की अपेक्षा विकास के इस भागदौड़ में सर्वोच्च शिखर पर स्थापित होगा।

इस मौके पर जदयू व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष अजित कुमार, जदयू पंचायत अध्यक्ष अशोक केशरी, युवा जदयू कार्यकर्ता संदीप रावत, नियाज खान अजित रावत, संजय सिंह, के अलावे कई कार्यरता एवं ग्रामीण अभियान में मौजूद थे।

राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूँ में सीटी स्कैन सुविधा का शुभारंभ

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इंतजार हुसैन

बदायूँ। राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूँ में अत्याधुनिक सीटी स्कैन सुविधा का शुभारंभ किया गया। यह सुविधा कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व राज्य मंत्री एवं सदर विधायक, भाजपा, शारदेन्दु पाठक, उपाध्यक्ष भाजपा बदायूँ जनपद, प्रो. (डॉ.) अरुण कुमार, प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूँ एवं डॉ. नेहा सिंह, उप-प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूँ द्वारा किया गया।

सीटी स्कैन मशीन आधुनिक फिलिप्स 128 स्लाइस हाई पावर मशीन है, जो बदायूँ जनपद की सबसे अत्याधुनिक और उच्च क्षमता वाली मशीन है। इस मशीन से विभिन्न चिकित्सा स्थितियों जैसे झ चोट, संक्रमण, ट्यूमर एवं आंतरिक असामान्यताओं का अधिक सटीक और त्वरित निदान संभव होगा।

मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांचों के लिए दर निर्धारित किए हैं:

बिना कॉन्ट्रास्ट: 600-1500 रुपया

कॉन्ट्रास्ट सहितः 2500 रुपया

यह सुविधा आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। प्रो. (डॉ.) अरुण कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूँ ने बताया कि हमारे संस्थान में सीटी स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधा शुरू होने से न केवल बदायूँ जनपद बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। आधुनिक और हाई पावर मशीन से समय पर व सटीक निदान संभव होगा, जिससे मरीजों के इलाज की गुणवत्ता और सफलता दर दोनों में वृद्धि होगी। हमारा प्रयास है कि मेडिकल कॉलेज में लगातार नई सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, ताकि आमजन को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ घर के नजदीक ही मिल सकें।

इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रितुज अग्रवाल, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. विपिन कुमार, डॉ. मुक्तयाज हुसैन, डॉ. अमित कुमार, विभागाध्यक्ष डॉ. सचिन यादव, सोशल मीडिया प्रभारी डॉ. लालेन्द्र यादव सहित शिक्षकगण एवं स्टाफ सदस्य झ शिबशंकर मौर्या, रिजवान, अमित कुमार आदि उपस्थित रहे।

राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूँ में इस सुविधा के प्रारंभ होने से पूरे जनपद एवं आसपास के क्षेत्र के मरीजों को आधुनिक और किफायती निदान की सुविधा मिलेगी।

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 पेश किया: नवाचार को बढ़ावा, नागरिकों की सुरक्षा

■ युवाओं और परिवारों को वित्तीय, मानसिक और सामाजिक खतरों से बचाएगा

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

गोरखपुर। पिछले 11 वर्षों में डिजिटल तकनीकों ने हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई भुगतान प्रणाली, 5जी कनेक्टिविटी और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ने मिलकर हमारे देश को एक नई पहचान दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, तकनीक के उपयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को अपार लाभ पहुँचाया है। इसी समय, विशेष रूप से डिजिटल क्षेत्र में नए जोखिम भी सामने आए हैं। इसीलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि समाज को तकनीक के दुरुपयोग से संभावित खतरों से बचाया जाए। इसी सोच के साथ, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 को आगे बढ़ाया है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है, जबकि हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और संबंधित वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाता है। विधेयक ऑनलाइन सट्टा और जुआ गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करता है-ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन जुआ (जैसे पोकर, रम्मी और अन्य कार्ड गेम) और ऑनलाइन लॉटरी तक। इसका उद्देश्य युवाओं को शिकार बनाने वाले ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप्स से बचाना है, जो भ्रामक पैसे लौटाने के वादों के जरिए उन्हें मजबूर और नशे की तरह खेलने पर विवश करते हैं, जिससे पूरा परिवार वित्तीय संकट में आ जाता है।

सरकार का मानना है कि नशे की लत, वित्तीय हानि और यहां तक कि आत्महत्या जैसी चरम स्थितियाँ, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी होती हैं, उन्हें इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर रोका जा सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक वित्तपोषण और संदेश गतिविधियों के लिए भी किया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करते हैं। साथ ही, यह विधेयक डिजिटल दुनिया

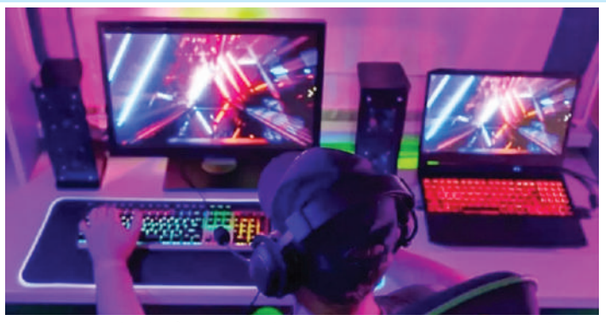

के राष्ट्रीय कानूनों को भौतिक दुनिया के मौजूदा कानूनों के साथ संरेखित करता है, जहाँ सट्टा और जुआ प्रतिबंधित या दंडनीय हैं-जैसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 और विभिन्न राज्य सरकारों के विधानों में।

ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय एक समर्पित ढांचा तैयार करेगा। ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और अन्य मंत्रालय जिम्मेदार होंगे।

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 के प्रावधान

1. ई-स्पोर्ट्स का प्रोत्साहन और मान्यता

ई-स्पोर्ट्स को भारत में प्रतिस्पर्धात्मक खेल के एक वैध रूप के रूप में मान्यता दी जाएगी।

खेल मंत्रालय ई-स्पोर्ट्स आयोजनों के संचालन हेतु दिशानिर्देश और मानक तैयार करेगा। ई-स्पोर्ट्स के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण अकादमियों, अनुसंधान केंद्रों और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों की स्थापना।

प्रोत्साहन योजनाएँ, जागरूकता अभियान और ई-स्पोर्ट्स का व्यापक खेल नीति पहलों में एकीकरण।

2. सामाजिक और शैक्षणिक खेलों का प्रोत्साहनः केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामाजिक खेलों को पहचानने, वगीर्कृत करने और पंजीकृत करने का अधिकार। सुरक्षित, आयु-उपयुक्त सामाजिक और शैक्षणिक खेलों के विकास और वितरण हेतु प्लेटफार्मों की सुविधा। सामाजिक खेलों की सकारात्मक भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम-मनोरंजन, कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता में। भारतीय मूल्यों के अनुरूप सांस्कृतिक और शैक्षणिक गेमिंग सामग्री का समर्थन।

3. हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंधः ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या सुविधा पर पूर्ण प्रतिबंध – चाहे कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हो।

सभी प्रकार के मीडिया में मनी गेम्स के विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध।

मनी गेम्स से जुड़े वित्तीय लेन-देन पर प्रतिबंध; बैंक और भुगतान प्रणाली ऐसे भुगतान की प्रक्रिया से रोकी जाएंगी।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अवैध गेमिंग प्लेटफार्मों की पहुँच ब्लॉक करने का अधिकार।

4. ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापनाः केंद्र सरकार राष्ट्रीय-स्तर का प्राधिकरण स्थापित करेगी या मौजूदा किसी प्राधिकरण/एजेंसी को निगरानी हेतु नामित कर सकेगी।

कार्यः ऑनलाइन गेम्स का वर्गीकरण और पंजीकरण।

यह निर्धारित करना कि कोई खेल मनी गेम है या नहीं।

ऑनलाइन गेम्स से संबंधित शिकायतों और विवादों का निपटान।

अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश, आदेश और आचार संहिता जारी करने का अधिकार।

5. अपराध और दंड

ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश या सुविधाः 3 साल तक की कैद और/या 1 करोड़ रु तक जुर्माना।

मनी गेम्स का विज्ञापनः 2 साल तक की कैद और/या 50 लाख रु तक जुर्माना।

मनी गेम्स से संबंधित वित्तीय लेन-देनः 3 साल तक की कैद और/या 1 करोड़ रु तक जुर्माना।

बार-बार अपराध पर कठोर दंडः 3-5 साल की कैद और 2 करोड़ रु तक जुर्माना।

प्रमुख धाराओं के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

6. कॉरपोरेट और संस्थागत दायित्वः कंपनियों और उनके अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जब तक वे उचित सावधानी सिद्ध नहीं करते।

स्वतंत्र निदेशकों या गैर-कार्यकारी निदेशकों को, जो निर्णय-निर्माण में शामिल नहीं हैं, संरक्षण दिया जाएगा।

7. जांच और प्रवर्तन की शक्तियाँ

केंद्रीय सरकार अधिकारियों को अपराधों से जुड़े डिजिटल या भौतिक संपत्ति की जांच, खोज और जब्ती के लिए अधिकृत कर सकती है।

अधिकारियों को कुछ मामलों में संदेहास्पद अपराधों की तलाशी लेने, खोजने और बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधान इस अधिनियम के तहत जांचों पर लागू होंगे।

8. नियम बनाने और प्रत्यायोजित कानून बनाने की शक्तियाँ

केंद्रीय सरकार को निम्न के लिए नियम बनाने का अधिकार होगाः

ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना। ऑनलाइन खेलों की पहचान, वर्गीकरण और पंजीकरण।

प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्यप्रणाली। कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक या अनुमत हो।

जेई ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कराई प्राथमिकी

एसबी ब्यूरो

मंसूरचक(बेगूसराय)। मंसूरचक बिजली विभाग के जेई हर्ष कुमार मौर्य ने मंसूरचक थाना में लिखित आवेदन देकर कहा कि मंगलवार को विधुत आपूर्ति प्रशाखा मंसूरचक कार्यालय में दिन के करीब एक बजे आशुतोष कुमार गुप्ता, पिता शिवशंकर गुप्ता वार्ड नंबर 04 गुरदासपुर थाना मंसूरचक के स्थाई निवासी हैं। जिसका उपभोक्ता संख्या 116207696874 है। इनके द्वारा कार्यालय आकर विधुत विपत्र गलत आने के बारे में बताया गया। जहां कार्यालय ने बताया गया कि आप एक आवेदन दे दिजिए आपके विधुत विपत्र से जो भी गड़बड़ी होगी उसे ठीक कर दिया जाएगा। इतने पर आशुतोष कुमार गुप्ता के द्वारा बोला गया कि अभी ठीक किजिए जबकी कार्यालय कर्मी के द्वारा पुनः दोहराया गया की आप एक बिल सुधार से संबंधित आवेदन जमा कर दिजिए स्थानीय मिस्त्री को भेजकर जांच करवा लिया जाएगा। इतने में आशुतोष कुमार गुप्ता गुस्से से आग-बबूला हो गए और अभद्र भाषा के साथ-साथ गाली गलौज करने लगे। किसी तरह अन्य विधुत कर्मी विनय कुमार, धर्मेंद्र झा, धर्मेन्द्र ठाकुर, रंजीत

साह और हाईपिंट के सुपरवाइजर अमित कुमार द्वारा समझा बुझाकर कार्यालय से बाहर किया गया। परंतु आशुतोष कुमार गुप्ता के द्वारा जाते-जाते यह बोला गया की बाहर निकलो बताते हैं।

वहीं जेई हर्ष कुमार मौर्य ने थानाध्यक्ष मंसूरचक से कोई अप्रिय घटना न घटे और आशुतोष कुमार गुप्ता के द्वारा सरकारी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं किया जा सके इसके लिए आशुतोष कुमार गुप्ता के उपर भारतीय अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की मांग की।

बेगूसराय में मारपीट कर अधमरा करने वाले दो आरोपित शिक्षक हुए सस्पेंड

एसबी ब्यूरो

बेगूसराय। बछवाड़ा प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जहांगपुर के शिक्षक आनन्द मोहन दास और बेगूसराय प्रखंड के मध्य विद्यालय लाखो के शिक्षक विश्वनाथ दास को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सस्पेंड कर दिया। बताया जाता है कि दोनों शिक्षक लाखो थाना कांड संख्याः 120/25 में आरोपित है। लाखो थाना क्षेत्र के मंझलापुर गांव के रहने वाले दोनों शिक्षक उसी गांव के स्व. रामप्रवेश दास के पुत्र राजीव कुमार को हाथ व पैर पोल में बांधकर पीटा था। घटना 7 जून 2025 की है। इस घटना में लाखो थाना की पुलिस ने दोनों शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था,वहीं बेहोशी की हालत में राजीव कुमार को सदर अस्पताल में इलाज कराया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दोनों शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए आनन्द मोहन दास को छौड़ाही और विश्वनाथ दास को मंसूरचक के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में निलंबन के दौरान योगदान करने का आदेश दिया। जारी पत्र के आलोक में दोनों शिक्षक के विरुद्ध बाद में प्रपत्र "क" निर्गत करने का निर्देश दिया गया।

मोहनलाल बडौली की उपस्थिति में चीका नगर पालिका की चेयरपर्सन भाजपा में शामिल

प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई भाजपा की सदस्यता

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। भाजपा के प्रदेश कार्यालय पंच कमल पंचकुला में नगरपालिका चीका की चेयरपर्सन डा. रेखा रानी को प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, प्रदेश भाजपा नेता अशोक गुज्जर, कैथल जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, जिला प्रभारी अमरपाल राणा व अन्य भाजपा के नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने भाजपा का पटका पहना कर विधिवत रूप से पार्टी में शामिल करवाया। रेखा रानी को भाजपा में शामिल करवाने में पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है।

इससे पूर्व 2014 में रेखा रानी ने गुहला विधानसभा का चुनाव आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था और 23 हजार वोट मिले थे तभी से एक मजबूत महिला नेत्री के तौर पर हल्के में अपनी पहचान रखती है। रेखा ने सीधे तौर पर नगरपालिका का चुनाव भाजपा -जजपा गठबंधन में लड़ कर विजय प्राप्त की थी। उनको नगरपालिका की कुर्सी पर बैठाने के लिए निवर्तमान सासंद व वर्तमान में मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी आए थे। रेखा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर भी कार्यरत रही है। रेखा रानी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों व कार्यशैली से बहुत प्रभावित है। देश व प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा ने विकास किया है व योजनाएं चलाई है उनसे हर वर्ग को मान सम्मान मिला है। भाजपा एक पार्टी ही नहीं, एक विचार है। वो एक विचार के साथ जुड़ कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। पहले देश फिर पार्टी फिर स्वयं की नीति के अनुसार भाजपा काम करती है।

रेखा ने कहा कि वो भाजपा पार्टी में दिन रात काम करेगी और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। रेखा ने कहा कि वो हल्के के हर भाजपा कार्यकर्ता के साथ मिल कर चलेगी और उन से पार्टी की रीती नीति को और बारीकी से जानेगी। रेखा ने भाजपा संगठन का पार्टी में शामिल करने पर आभार प्रकट किया और भरोसा दिलाया कि वो पार्टी के लिए मेहनत करेगी।

जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए गंभीरता से करें कार्य: एडीसी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। बुधवार को लघु सचिवालय में कुपोषण मुक्त अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने कहा कि जिले को कुपोषण से मुक्त करने के लिए सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। हम सबको मिलकर जिला को कुपोषण मुक्त बनाना है। इसलिए इसमें सभी की सक्रिय भागीदारी होने चाहिए। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने सर्कल अनुसार कुपोषित बच्चों से संबंधित जानकारी ली तथा स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कुपोषित बच्चों के आंकड़ों का आंकलन किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को आदेश दिए कि आरबीएसके की टीम द्वारा चिन्हित किए गए कुपोषित बच्चों को फॉलो अप समय-समय पर किया जाए, ताकि उनको कुपोषण श्रेणी से सामान्य श्रेणी में लाया जा सके। सभी सुपरवाइजर पोषण ट्रेकर पर अपना डाटा दुरूस्त करवाएं।

इस मौके पर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी शशि बाला, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. विकास धवन, कुलदीप आदि मौजूद रहे।

जीवन चानन महाविद्यालय में दीक्षारंभ कार्यक्रम का किया आयोजन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग असन्ध। जीवन चानन स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉ. सिमरत पाल के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवागंतुक छात्राओं को महाविद्यालय के नियमों की जानकारी देना व महाविद्यालय से परिचित करवाना होता है। ताकि छात्राओं को भविष्य में कोई कठिनाई न हो। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. रेखा शर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय उच्च मापदडं एवं मानकों के अनुसार छात्राओं को शिक्षा देने का प्रयास करता रहेगा। उन्होंने छात्राओ को विभिन्न कौशलों में व्यवहार कुशलता लाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ-साथ उन्होंने आत्मरक्षा प्रशिक्षण के विषय में पूरी जानकारी दी। उन्होंने खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ाने की भी बात कही और जो छात्राएं यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना चाहती है। उन छात्राओं का महाविद्यालय से उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे कोर्स शुरू करने की बात कही ताकि छात्राएं भविष्य में उनका लाभ उठा पाएं। उन्होंने कहा कि छात्राएं अनुशासन में रहते हुए कठिन परिश्रम और तन्मय होकर अध्ययन करें ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

डॉ. रेखा बंसल, सुषमा शर्मा ने छात्राओं को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति एवं माई भारत पोर्टल व इंटर्नशिप की जानकारी विस्तार से दी। मनीषा फौगाट ने राष्ट्रीय सेवा योजना, सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति के बारे में छात्राओं को विस्तार बताया। डॉ. हेमलता शर्मा ने रैड क्रॉस, रेड रिबन क्लब की विस्तार से जानकारी छात्राओं को दी। डॉ. सिमरत पाल ने एंटी रैगिंग, युवा एवं सांस्कृतिक विभाग की जानकारी छात्राओं को प्रदान की। डॉ. नीतू सेठी ने कैंटीन वह एजुकेशनल टूर के बारे में जानकारी दी। केडी शर्मा ने भी छात्राओं को जानकारी दी। राजविंदर ने महिला प्रकोष्ठ के बारे में छात्राओं को बताया। इस अवसर पर महाविद्यालय के निदेशक रमेश बत्रा, महासचिव सुशील गर्ग व अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

डीएसपी ट्रैफिक ने डॉ. बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय कैथल में विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए किया जागरूक

चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जान माल की सुरक्षा के लिए करें यातायात नियमों की पालना: डीएसपी

एसबी संवाददाता

कैथल। सड़क सुरक्षा विषय के तहत एसपी आस्था मोदी के आदेशानुसार आमजन सहित युवाओं को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए बुधवार को डॉ. बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय कैथल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक सुशील प्रकाश व यातायात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा दुर्घटनाओं में कमी लाना है। डीएसपी सुशील प्रकाश ने विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की आवश्यकता, हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग, तेज गति और मोबाइल के उपयोग से होने वाले खतरों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही और नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं, जिन्हें थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से रोका जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान आईटीआई स्टाफ व विद्यार्थियों को फोटो के माध्यम से बताया कि बहुत सारे आईटीआई के विद्यार्थी दुपहिया पर तीन सवारी व बिना हेलमेट के चलते है।

डीएसपी ने कहा कि चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी व दुसरों की जान माल की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए।

ट्रैफिक नियमों के बारे विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए डीएसपी सुशील प्रकाश। (छाया: एसबी)

कृषि मंत्री ने सुनी जन समस्याएं

एसबी संवाददाता/चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर जिला के गांव दुधला में लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर श्री राणा ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि हर वर्ग का कल्याण हो और हर पात्र व्यक्ति को सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है और वे सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच पहुंचे है। उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में विकास के शिखर को छू रहा है और यह तभी संभव हो पाया है जब देश की कमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। आज विश्व के दूसरे देश भारत की ओर मदद की दृष्टि से देखते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों एवं योजनाओं की विश्व के दूसरे देशों में सराहना हो रही है। इससे हर भारतीय का दुनिया में मान-सम्मान बढ़ा है।

मनीषा हत्याकांड में सुलग रहा है हरियाणा

हत्यारों की फांसी की मांग को लेकर राजौंद में निकाला गया कैंडल मार्च

राजौंद में सैकड़ों युवाओं ने हाथों में मोमबत्ती व बैनर, तख्तियां लेकर निकाला मार्च, गूंजे इंसाफ के नारे

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार राजौंद। जिला भिवानी की बेटी शिक्षिका मनीषा की हत्या होने के पश्चात पूरा हरियाणा सुलग रहा है। मनीषा हत्याकांड को लेकर बेटी के हत्यारों को पकड़ कर फांसी की सजा दी मांग की जा रही है। राजौंद क्षेत्र में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। बुधवार शाम सात बजे राजौंद के सरकारी अस्पताल के मुख्य द्वार से महाराणा प्रताप चौक, पूंडरी मोड तक सैकड़ों युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर हत्यारों को पकड़ने व फांसी देने की मांग की kयुवाओं के हाथों में जलती मोमबत्तियां और मनीषा को इंसाफ दिलवाओ लिखे बैनर थे। मार्च के दौरान मनीषा को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे गूंजते रहे। माहौल गमगीन होने के साथ-साथ लोगों के चेहरे पर आक्रोश भी साफ दिखाई दिया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। युवाओं ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और अदालत से फांसी की सजा दिलाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार व प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

युवाओं ने कहा कि बेटियों के साथ हो रहे अपराध समाज पर कलंक हैं। यदि ऐसे अपराधियों को कठोर सजा नहीं दी गई तो अपराध और बढ़ेंगे। इसलिए दोषियों को फांसी की सजा देना आवश्यक है ताकि समाज में भय और अनुशासन कायम हो सके।

कैंडल मार्च महाराणा प्रताप चौक से पुनः शुरू हो कर इंसाफ की मांग करते हुए नगर की गलियों, बाजार से होते हुए नगर के कैथल मार्ग पर स्थित सरकारी अस्पताल पर पहुंचकर बेटी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकरआंदोलन का समापन हुआ। इस दौरान स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और एक स्वर में न्याय की मांग उठाई।

> गुरनाम सिंह चढूनी ने बताया कि मनीषा बेटी का अंतिम संस्कार कल वीरवार, 21 अगस्त को सुबह 8 बजे किया जाएगा। गांव की पंचायत के बीच यह फैसला लिया गया है। अब ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया है। सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने पीड़ित परिवार की दोनों मांग मानते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने व मृतका का दिल्ली AIIMS में तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाने की बात मान ली है। गुरनाम सिंह चढूनी ने बताया कि जांच जल्द CBI को सौंपी जाएगी। बुरात 9 बजे बाद आएगा मनीषा का शव भिवानी। पंचायत में परिवार से पिता और दादा ने भी सहमति जताई।

राजौंद में ब्रह्माकुमारीज आश्रम द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार राजौंद। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में ब्रह्माकुमारीज संस्था द्वारा विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक यूनिट रक्त एकत्र करने का संकल्प लिया गया है, जिससे विश्व कीर्तिमान स्थापित होगा। इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की तैयारी है।

इसी श्रृंखला में राजौंद के सुख शांति भवन, कैथल रोड स्थित सेवा केंद्र पर 24 अगस्त 2025, रविवार प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। हरियाणा सहित देशभर के हजारों सेवा केंद्र इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि रक्तदान करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, क्योंकि एक यूनिट रक्त किसी असहाय व जरूरतमंद को जीवनदान दे सकता है। किसी परिवार के लिए यह नया सवेरा और खुशियों की वापसी का कारण बन सकता है। आश्रम पदाधिकारी बीके आशा ने युवाओं और समाज के हर वर्ग से आह्वान किया कि वे इस महान कार्य में भाग लेकर मानवता की सेवा में योगदान दें। रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति पहले से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण हेतु ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया गया है।

स्थान-ब्रह्माकुमारीज सुख शांति भवन, गुरुद्वारा के पास, कैथल रोड, राजौंद, अधिक जानकारी के लिए संस्था के जारी मोबाइल फोन नम्बर पर संपर्क किया जा सकता है: 9729057418

प्रवक्ता ने अपील करते हुए कहा कि "आपका एक छोटा-सा योगदान किसी को जीवन दे सकता है। आइए, रक्तदान कर-के मानवता की सेवा में भागीदार बनें।"

डेंगू से बचाव के लिए साफ-सफाई का रखें विशेष ध्यान

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की जनता का आह्वान किया है कि वे अपने आसपास व घरों के अन्दर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में मक्खी-मच्छर पनपते हैं जिन्हें रोकने के लिए साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर रुके हुए गंदे पानी में पैदा होते हैं, जबकि डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं। सभी व्यक्ति पानी की टंकियों को समय-समय पर अच्छी तरह साफ करके पूरी तरह ढक कर रखें।

उन्होंने सलाह दी कि डेंगू होने पर अचानक तेज बुखार; खासकर कुछ दिन बाद कम होकर फिर से तेज बुखार आना, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों तथा जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, थकान होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में सम्पर्क करें और जांच करवाएं। चिकित्सक की सलाह से ही दवा खाएं। उन्होंने बताया कि घर के आस-पास सफाई रखें, घरों के अन्दर व आस-पास के गड्ढों में पानी एकत्रित न होने दें। यदि कूलर प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है तो उसमें पानी एकत्रित न होनें दें।

फ्रिज के नीचे रखी हुई पानी एकत्रित करने वाली ट्रे को भी प्रतिदिन खाली कर दें। गड्ढों को मिट्टी से भर दें। रुकी हुई नालियों को साफ रखें ताकि उनमें पानी ठहर न सके और मच्छरों को पनपने का मौका न मिल पाए। हर रविवार घर और आस पास के क्षेत्र की सफाई करके शुष्क दिवस (ड्राई डे) मनाएं।

हरियाणा में सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा हॉरिजॉन्टल आरक्षण

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के निवासी पूर्व-अग्निवीरों को सीधी भर्ती में क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस विषय पर सरकार द्वारा गहन विचार-विमर्श करने के बाद, अब एक नीति बनाकर राज्य की विभिन्न सेवाओं में पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। इस नीति के अनुसार, कौशल-विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी के पदों पर पूर्व-अग्निवीरों को 1 प्रतिशत तथा ग्रुप-सी के पदों (कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) पर 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डर तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

सभी सामाजिक वर्गों में न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण निश्चित रोस्टर बिंदुओं पर लागू किया जाएगा। चयन पूर्णतः मैरिट के आधार पर होगा और पूर्व-अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित वर्टीकल श्रेणी में आरक्षित पदों के विरुद्ध किया जाएगा। यदि उपयुक्त पूर्व-अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्त पद को संबंधित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक जांच परीक्षा से छूट दी जाएगी, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता और सैन्य प्रशिक्षण पहले से प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त, पूर्व-अग्निवीरों को पहले से ही ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से छूट दी गई है। उन्हें अपने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल-विशेषज्ञता से संबंधित परीक्षा से भी छूट मिलेगी।

नव नियुक्त चौकी इंचार्ज रोहतास ने संभाला कार्यभार

संजना भारती संवाददाता

असंध। बल्ला पुलिस चौकी में रोहतास ने चौंकी इंचार्ज का पदभार संभाला। नए चौकी इंचार्ज रोहतास का स्वागत ग्रामीणों ने गुलदस्ता देकर किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने स्टाफ से परिचय किया और लंबित मामलों की जानकारी ली। चौकी इंचार्ज ने क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने की अपनी प्राथमिकताएं सांझा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रात्रि में संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाएगी और तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौकी इंचार्ज ने स्पष्ट तौर पर कहां की क्षेत्र में किसी प्रकार के नशे की तस्करी नहीं होनी चाहिए। हम सब का दायित्व बनता है कि नशे की सप्लाई करने वालों पर कड़ी नजर रखें। क्षेत्र में अगर किसी जगह नशे आदि की बिक्री होती है तो उन्हें तुरंत सूचित करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ऐसी सामाजिक बुराई से बचाया जा सके और जो युवा नशे में संलिप्त है उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

वन मित्र योजना से प्रदेश में बढ़ेगा पौधारोपण: राव नरबीर सिंह

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने के लिए वन मित्र योजना को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अब वन मित्र केवल निजी भूमि पर ही नहीं, बल्कि वन विभाग की भूमि पर भी गड्ढे खोदकर पौधारोपण कर सकेंगे।

मंत्री ने ये निर्देश आज चंडीगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

वन मंत्री ने स्पष्ट किया कि वन मित्रों को दिए जाने वाले 15 हजार रुपये मासिक मानदेय में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और इसे तुरंत जारी किया जाए। बैठक में मंत्री को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2024 में शुरू की गई वन मित्र योजना के तहत 70 हजार युवाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया था तथा उन्होंने दो लाख से अधिक गड्ढे खोदे, जिसमें से 10 गड्ढों में पौधारोपण कर जियो टैगिंग के बाद 2598 युवाओं को वन मित्र का दर्जा दिया गया। मंत्री ने निर्देश दिए कि अब जियो टैगिंग के बजाय डीएफओ, कंजरवेटर और फॉरेस्ट गार्ड व्यक्तिगत रूप से गड्ढों और पौधारोपण का सत्यापन एवं मॉनिटरिंग करेंगे। इससे वन मित्रों के कार्य का सही मूल्यांकन हो सकेगा और उनका मानदेय डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी ढंग से जारी किया जा सके।

हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश को हरियाली और स्वच्छ वायु का प्रदेश बनाया जाए। सरकार एक पेड़ मां के नाम के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ रही है, ताकि हरियाणा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा-भरा और स्वस्थ प्रदेश बन सके।